# डॉक्टरों ने ममता का वार्ता प्रस्ताव ठुकराया

## मुख्यमंत्री ने गतिरोध सुलझाने के लिए बुलाई थी बैठक, डॉक्टरों ने पत्र की भाषा को बताया अपमानजनक

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने वार्ता के लिए भेजा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। डॉक्टरों ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल की भाषा को अपमानजनक बताया और इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे पहले उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय का काम पर लौटने का आदेश भी नहीं माना। अदालत ने उन्हें मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौटने को कहा था।

मंगलवार शाम को राज्य के स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को भेजे ईमेल में कहा, 'आपका छोटा प्रतिनिधिमंडल (अधिकतम 10 व्यक्ति) अब सरकारी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए 'नबान्न' (राज्य सचिवालय) आ सकता है।'

उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी (एनएस निगम) को वे हटाने की मांग कर रहे हैं, वही उन्हें बैठक के लिए पत्र भेज रहे हैं, यह बहुत अपमानजनक है। डॉक्टरों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी साथी डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता और उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के सामने धरने का आह्वान करने वाले डॉक्टर देबाशीष हलदर ने कहा, 'बैठक के लिए भेजे गए पत्र की भाषा न केवल अपमानजनक है, यह असंवेदनशील भी है। इस ईमेल का जवाब देने का कोई कारण नजर नहीं आता।' डॉक्टरों ने कहा कि हालांकि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।

डॉक्टरों का आंदोलन मंगलवार को 32वें दिन में प्रवेश कर गया है। वे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। गतिरोध को सुलझाने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार शाम आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों को राज्य सचिवालय में बैठक के लिए आमंत्रित किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि बैठक के लिए ईमेल उन्हीं राज्य स्वास्थ्य सचिव द्वारा भेजा गया है, जिनके इस्तीफे की मांग डॉक्टर पिछले एक महीने से कर रहे हैं। यह अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल दस डॉक्टरों को बैठक के लिए बुलाना अपमानजनक बात है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया, 'हमारा विरोध प्रदर्शन और हमारा 'काम बंद' जारी रहेगा।'

इस बीच, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, 'मुख्यमंत्री कनिष्ठ चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल के बैठक में आने का अपने कक्ष में इंतजार कर रही हैं।' खबर लिखे जाने तक ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बैठक नहीं हो पाई थी।

शीर्ष अदालत ने एक दिन पहले सोमवार को प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों को मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौटने का निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। न्यायालय ने यह निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद दिया था कि काम पर लौटने पर प्रदर्शनकारी चिकित्सकों के खिलाफ दंडात्मक तबादलों सहित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आंदोलनकारी चिकित्सकों ने कहा, 'हमने राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को शाम पांच बजे तक पद से हटाने को कहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। 'हमारी मांगें पूरी नहीं होने के कारण हम काम बंद रखेंगे। हालांकि हम चर्चा के लिए तैयार हैं।'इस बीच, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने धमकी की संस्कृति को बढ़ावा देने और संस्थान के लोकतांत्रिक माहौल को खतरे में डालने के लिए 51 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 11 सितंबर को जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें समिति के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

आरजी कर अस्पताल की विशेष परिषद समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उन 51 डॉक्टरों के लिए संस्थान के परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित है, जब तक कि जांच समिति द्वारा उन्हें नहीं बुलाया जाता। अस्पताल के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है इन डॉक्टरों के कॉलेज की गतिविधियों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सूची में वरिष्ठ रेजिडेंट, हाउस स्टाफ, इंटर्न और प्रोफेसर शामिल हैं।

कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन तक विशाल रैली निकाली फोटो-पीटीआई

- प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने नहीं माना सर्वोच्च न्यायालय का मंगलवार तक काम पर लौटने का आदेश
- अफसरों को हटाने की मांग पूरी होने व पीड़ित को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
- अस्पताल में धमकी की संस्कृति को बढ़ावा देने और माहौल खराब करने के लिए 51 डॉक्टरों को नोटिस

### पूर्व प्राचार्य न्यायिक हिरासत में

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। **भाषा**

# शोध क्षेत्र की बाधाएं दूर करें: प्रधानमंत्री

बीएस संवाददाता

**प्रधानमंत्री** नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समस्याएं वैश्विक प्रकृति की हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान भारतीय जरूरतों के अनुसार स्थानीय स्तर पर होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) की अपने निवास पर आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए बड़े लक्ष्य तय करने, उन्हें हासिल करने पर ध्यान देने और पथप्रदर्शक शोध करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक बैठक में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य और अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के पुनर्निधारण के बारे में चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एएनआरएफ की स्थापना वर्ष 2023 में देश के तमाम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास के प्रसार तथा शोध एवं नवोन्मेष की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक शोध को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा देने वाले शीर्ष संस्थान के तौर पर काम करता है। बैठक के दौरान शासी निकाय ने हब एंड स्पोक मोड में एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें उन विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा जहां अनुसंधान प्रारंभिक चरण में है।

एएनआरएफ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

# येचुरी की हालत 'गंभीर'

**मार्क्सवादी** कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी की हालत 'गंभीर' है और उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया है। उनकी पार्टी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि 72 वर्षीय येचुरी का एम्स की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में तीव्र श्वसन नली संक्रमण का उपचार किया जा रहा है। **भाषा**

# बुच को तलब करने की मांग भाजपा ने की आपत्ति

**तृणमूल** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने मंगलवार को हितों के टकराव के आरोपों का सामना कर रहीं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष तलब करने की मांग की।

'जल जीवन मिशन' के कामकाज के ऑडिट के लिए बुलाई गई बैठक में रॉय ने कहा कि बुच को समिति के सामने पेश होना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि हालांकि, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह नियमों के खिलाफ है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में दुबे ने कहा कि सीएजी के प्रधान लेखा परीक्षक केंद्र सरकार के आदेश के बिना सेबी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पीएसी भी नियामकों के अधिकारियों को वित्त संबंधी 'खामियों' के सबूत के बिना नहीं बुला सकती। दुबे ने कहा कि सबसे पुरानी संसदीय समिति होने के नाते पीएसी के अपने परिभाषित नियम हैं और यदि स्वतः संज्ञान लेना है तो उसे साक्ष्य के साथ प्रमाणित करना होगा। **भाषा**

# चीन के साथ कारोबार के दरवाजे बंद नहीं : जयशंकर

**विदेश** मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन में एक बयान में कहा कि भारत ने चीन के साथ व्यापार बंद नहीं किया है, लेकिन मुद्दा यह है कि चीन के साथ किन क्षेत्रों में और किन-किन शर्तों पर व्यापारिक साझेदारी की जाए। दोनों देशों के बीच जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। उस समय सीमा पर दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 तथा चीन के 4 सैनिक मारे गए थे।

भारत ने उसके बाद से चीनी कंपनियों के निवेश पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी थी, जिससे कई बड़ी परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने इस बात की वकालत की थी कि देश में और अधिक निवेश को मंजूरी दी जानी चाहिए।

बीते जुलाई में जारी ताजा वार्षिक आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि अपने वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत या तो चीन की सप्लाई चेन के साथ साझेदारी में काम करे अथवा चीन से आने वाले निवेश को बढ़ाए। बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा, 'हम चीन से कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मुद्दा यह है कि किन क्षेत्रों और किन शर्तों पर यह कारोबार हो।' **भाषा**

विदेश मंत्री जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री फोटो-पीटीआई

## रूस-यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी, भारत सलाह देने को इच्छुक

युद्ध के मैदान में यूक्रेन संघर्ष का समाधान नहीं हो सकने का दावा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी ही होगी और यदि वे सलाह चाहते हैं तो भारत सलाह देने का सदैव इच्छुक है। जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। एक दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी में भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ 'सार्थक वार्ता' की थी। उन्होंने कहा, ' हमें नहीं लगता है कि इस संघर्ष का युद्ध के मैदान में हल होने वाला है। कहीं न कहीं, कुछ बातचीत तो होगी ही। जब कोई बातचीत होगी, तो मुख्य पक्षों - रूस और यूक्रेन - को उस बातचीत में शामिल होना ही होगा।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस एवं यूक्रेन यात्राओं का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय नेता ने मॉस्को और कीव में कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमें नहीं लगता है कि आपको रणभूमि में कोई समाधान मिलने जा रहा है। हमारा मानना है कि आपको बातचीत करनी होगी, यदि आप सलाह चाहते हैं तो हम उसे देने के लिए सदैव इच्छुक हैं।'

# मोदी भय अब 'इतिहास' : राहुल

**कांग्रेस** नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस बार भारत में आम चुनाव के नतीजों ने 'मोदी का विचार' ध्वस्त कर दिया और प्रधानमंत्री द्वारा पैदा किया गया 'डर' गायब हो गया तथा 'इतिहास' बन गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल अभी अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने सोमवार को वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और वाशिंगटन डीसी के वर्जीनिया के एक उपनगर हर्नडॉन में एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई में सत्तारूढ़ गठबंधन ध्वस्त हो गया, 'एकदम बीच से' टूट गया। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद चीजें बदल गई हैं। उन्होंने कहा, 'मोदी जी द्वारा पैदा किया डर एक सेकंड में गायब हो गया। उस डर को पैदा करने में कई साल लग गए, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई और काफी पैसा लगाया गया लेकिन इसे खत्म होने में केवल एक सेकंड लगा।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लोकसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाई लेकिन भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला।

अमेरिका में राहुल गांधी

# 'सिख समुदाय पर राहुल की टिप्पणी भयावह'

**भाजपा** ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में 'संवेदनशील मुद्दों' पर बोलकर 'खतरनाक विमर्श' गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल की टिप्पणी 'भयावह' है क्योंकि उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की। सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता ने कहा, 'सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने के बारे में उनके द्वारा की गई टिप्पणी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।'

कांग्रेस के शासनकाल में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा, 'हमारे इतिहास में अगर कोई समय रहा है जब एक समुदाय के रूप में हमने चिंता, असुरक्षा की भावना और अस्तित्व के खतरे को महसूस किया है तो यह ऐसा समय था जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था।' उन्होंने कहा, 'वर्ष 1984 में सिख समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया गया था। 3,000 निर्दोष लोग मारे गए। लोगों को घसीटकर उनके घरों से बाहर निकाला गया, उनके गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया गया।'

वाशिंगटन के वर्जीनिया उपनगर में हर्नडॉन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसी बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा, 'सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है।' राहुल ने वहां पहली पंक्ति में दर्शकों के बीच बैठे एक सिख व्यक्ति से पूछा, 'मेरे पगड़ीधारी भाई आपका क्या नाम है।' कांग्रेस नेता ने कहा, 'लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है।' **भाषा**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पात्र तथा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं / बोलीदाताओं से **आरएफपी-41/2024-25 सक्रिय निर्देशिका प्रबंधन और रिपोर्टिंग टूल की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव** हेतु मुहरबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofmaharashtra.in** पर 'टेंडर सेक्शन' में **तथा जेम पोर्टल https://gem.gov.in** पर दिनांक 10.09.2024 से उपलब्ध रहेगी।

**आरएफपी संख्या: आरएफपी - 41/2024-25**

**बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 04.10.2024, 17:00 hrs.**

इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त साइट से आरएफपी दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाओं से संबंधित सभी अन्य अपडेट **GeM** पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ह/-

दिनांक : 10/09/2024 महाप्रबंधक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

# हरियाणा: भाजपा ने दो मंत्रियों के टिकट काटे

## विनेश के खिलाफ जुलाना से बैरागी को उतारा

**भारतीय** जनता पार्टी (भाजपा) ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें दो मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं जबकि पिहोवा सीट से उम्मीदवार को बदल दिया गया है। हरियाणा में सत्तारूढ़ पार्टी ने महेंद्रगढ़, एनआईटी फरीदाबाद और सिरसा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट से मुकाबले के लिए पार्टी ने युवा नेता कैप्टन योगेश बैरागी पर दांव खेला है।

भाजपा ने 4 सितंबर को जारी अपनी पहली सूची में कमलजीत सिंह अजराना को पिहोवा सीट से उम्मीदवार बनाया था लेकिन दूसरी सूची में उनकी जगह जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया है। पार्टी ने पिहोवा के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट काट दिया था। अजराना को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्हें स्थानीय कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने मंत्री बनवारी लाल का भी टिकट काट दिया है और उनकी जगह कृष्ण कुमार को मैदान में उतारा। बढकल की मौजूदा विधायक और स्कूल शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह धनेश अदलखा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।

हालांकि, सोहना से विधायक और एक अन्य मंत्री संजय सिंह को नूंह से टिकट दिया गया है। पार्टी ने तेजपाल तंवर को सोहना से मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ दल ने गन्नौर, पटौदी, हथीन और होडल सीटों से मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और नए चेहरों पर भरोसा जताया है। हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली ने स्पष्ट कर दिया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसके बजाय पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। इसके मद्देनजर राई विधानसभा क्षेत्र से कृष्णा गहलावत को उम्मीदवार बनाया गया है। पटौदी (अनुसूचित जाति) सीट से बिमला चौधरी को टिकट मिला है। **भाषा**

# मणिपुर में छात्रों का उग्र प्रदर्शन

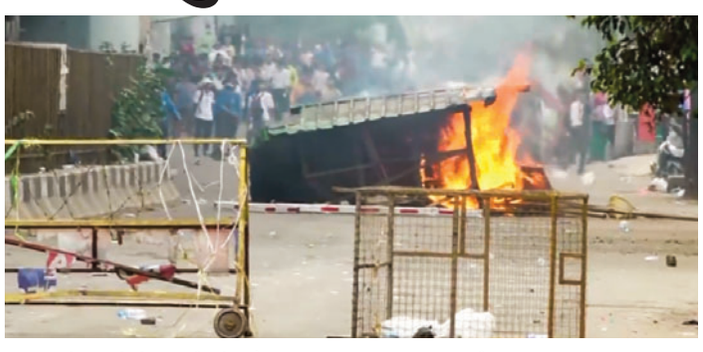

इंफाल में छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान सड़क पर आग लगाई फोटो-पीटीआई

**मणिपुर** के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और राज्य के सुरक्षा सलाहकार को पद से हटाने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच करने के प्रयास के दौरान, सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 40 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हजारों छात्रों और महिला प्रदर्शनकारियों ने बी टी रोड पर राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें कांग्रेस भवन के पास रोक दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर और कंचे फेंके, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े।

मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी विरोध रैली निकाली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। अधिकारी ने बताया कि बाद में वे राज्य सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें इंफाल पश्चिम जिले के काकवा में रोक दिया गया। छात्र मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में कथित रूप से अक्षम रहने को लेकर डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि झड़पों में 40 से अधिक छात्र घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके तहत लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। वहीं, थौबल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इस बीच, मणिपुर सरकार ने छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच मंगलवार को पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं को पांच दिन के लिए निलंबित कर दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय तस्वीरों, नफरती भाषण और घृणास्पद वीडियो के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने जातीय संघर्ष प्रभावित मणिपुर में सुरक्षा ड्यूटी के लिए करीब 2,000 कर्मियों वाली दो और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) बटालियनों की तैनाती का भी निर्देश दिया है। **भाषा**

www.bankofbaroda.in बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

डिजिटल चैनल एवं परिचालन, बड़ौदा भवन, वडोदरा

निविदा सूचना

डिजिटल साइनेज सिस्टम (डीएसएस) की आपूर्ति, इन्स्टॉलेशन और रखरखाव हेतु वेंडर के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध आमंत्रित हैं।

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड और सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर उपलब्ध है।

'अन्य सूचना', यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड तथा सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर जारी किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ता इसे अवश्य देख लें।

**निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर, 2024 है।**

स्थान: वडोदरा मुख्य महाप्रबंधक

दिनांक: 11.09.2024 (डिजिटल चैनल एवं परिचालन) 71/24-25

www.bankofbaroda.in बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सूचना सुरक्षा विभाग, मुंबई सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से बैंक के इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशन, इंट्रानेट एप्लीकेशन और इसके बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा जोखिमों के आकलन और खामियों के परीक्षण के लिए सेवा प्रदाता के चयन हेतु निविदाएं आमंत्रित करता है।

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। निविदा में संशोधन सहित भी अन्य सूचना / शुद्धिपत्र को केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बोलीकर्ता अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) निविदा संदर्भ संख्या: GEM/2024/B/5371843

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: **01-अक्तूबर-2024 15:00 बजे** तक (भारतीय समयानुसार)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 11.09.2024 समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी 70/24-25